nt>

16.04 hrs.

Title: Statement regarding potato price in the country.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): Sir, the total production of potatoes in the country is expected to be around 24 million metric tonnes during the current year. The annual production ranges from 17 million to about 24 million metric tonnes. The major potato producing States in the order of production are Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Karnataka and Punjab which put together account for 85 per cent of total potato production. It has been reported that the price of potato in Uttar Pradesh and West Bengal are ruling in the range of Rs.130 to Rs. 170 per quintal against the production cost of Rs. 190 to Rs. 210 per quintal. The Government of Uttar Pradesh has reported an estimated production of potato of 102 lakh metric tonnes during 2002-2003 as compared to 95.70 lakh tonnes in 2001-2002 and 83.98 lakh metric tonnes in the year 2000-2001.

The rate of fair quality potato was reported to be ruling between Rs. 138 and Rs. 239 per quintal against the cost of production of Rs. 190 per quintal. In view of the prevailing low prices of potatoes which are even lower than the cost of production, the Government of Uttar Pradesh requested the Ministry of Agriculture to consider the procurement of potato under Market Intervention Scheme during the current season. I took a meeting on 5th February 2003 with the State Government at Lucknow for implementation of MIS for procurement of potato in Uttar Pradesh. It was decided to procure one lakh metric tonnes of potato in the State. It was also decided that 50,000 metric tonnes would be procured by the NAFED and 50,000 metric tones would be procured by the State-designated agencies.

* Also placed in Library, See No. LT. − 7333/2003

The State Government of Uttar Pradesh sent a proposal on 7th February 2003 for implementation of MIS for procurement of one lakh metric tonnes of potato which was discussed in a meeting held on 11th February with the State Government officers. The State Government reported the cost of production of fair average quality potatoes at Rs. 190 per quintal. After considering the proposal of the State Government, the Central Government sanctioned MIS for potato in Uttar Pradesh for a quantity of one lakh metric tonnes at the rate of Rs. 190 per quintal. Out of one lakh metric tonne, NAFED was to procure 50,000 metric tonnes while 50,000 metric tonnes were to be procured by the designated agencies. The NAFED and the State agencies have opened centres in 24 districts for procurement of potato in Uttar Pradesh under MIS. Procurement operations have commenced. It has been reported that NAFED has so far procured 1750 quintals of potatoes in Uttar Pradesh under this Scheme. In addition, 5,000 quintals of potatoes have also been purchased by the NAFED from Uttar Pradesh under their normal business operations.

The Government of West Bengal has submitted a proposal for implementation of MIS for procurement of potato which was considered by the Committee in this Department on 7th of April 2003. MIS for a quantity of 20,000 metric tonnes at the cost of Rs. 200 per quintal has been recommended by the Committee as requested by the West Bengal Government. Out of the 20,000 metric tonnes, the NAFED will procure 10,000 metric tonnes and the balance 10,000 metric tonnes will be purchased by the BANFED -- the State Government agency. As reported, the BANFED has already started the procurement of potato in West Bengal. No request from any other State Government has come so far for starting procurement under MIS.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, मुझे आपकी मार्फत माननीय कृषि मंत्रीजी से बृहम आग्रह करना है। मैंने 11 मार्च को ध्यानार्काण प्रस्ताव के द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्ति किया था। मेरे प्रश्न के जवाब में उस समय जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था, वही जवाब कृषि मंत्री जी आज दे रहे हैं। उन्होने खुद स्वीकार किया था कि पिछले वर्ा की तुलना में इस वर्ा आलू का रिकार्ड उत्पादन होगा, एक लाख मिट्रिक टन आलू सरकार खरीदेगी और 50 हजार मिट्रिक टन आलू नाफैड खरीदेगा। â€¦(व्यवधान)हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैंâ€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूंâ€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सीधे प्रश्न पूछ लीजिए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : आप प्रश्न थोड़ा मुस्कराकर पूछ लीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : मुस्कराकर अगली बार पूछ लेंगे।

सभापति महोदय : आप क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। â€¦ (व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि इस दिशा में कोई सकारात्मक प्रयास कृषि मंत्री करें। अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कहा गया था कि 24 सैंटर्स खोले जाएंगे लेकिन वे समय पर नहीं खुले। आज के अखबार में छपा है कि " आगरा में आलू की खरीद आज से " कुल मिला कर जिन सैंटर्स के खोलने की बात थी, उन्हें खोला नहीं गया। इलाहाबाद सैंटर में 190 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीदने की बात थी। मैं कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आलू का बुरा हाल है। आलू खेतों में सड़ रहे हैं। किसान अब आलू बोने को तैयार नहीं हैं। उन्हें 190 तो क्या 100 रुपए के भाव भी नहीं मिल रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। एक-दो किसानों ने इसे लेकर खुदकुशी भी कर ली है।

सभापति महोदय : आप यह बात सुबह भी बोल चुके हैं। आप केवल क्लैरिफिकेशन्स लें।

श्री रामजीलाल सुमन : कृषि मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि क्या उत्तरप्रदेश में सही मायने में केन्द्र खुले हैं या नहीं? यदि केन्द्र खुले हैं तो वहां इसका जो भाव दिया जा रहा है, वह कितना है? इस बार किसानों की हालत खराब होने का प्रमुख कारण यह था कि पूरे समाज में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ा कि खाड़ी के देशों में जो आलू का निर्यात होना था, वह नहीं हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि वहां कितना निर्यात हुआ? इस बारे में जो वायदा किया गया था, उसे लेकर किसान आस लगाए बैठे हैं। यदि उनका आलू बाहर जाएगा तो उनके हित सुरक्षित रहेंगे। यदि इन सवालों पर कृषि मंत्री जी वक्तव्य दें तो बड़ी कृपा होगी।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदयः स्टेटमैंट के बाद कोई क्वैश्चन नहीं हो सकते हैं।

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Mr. Chairman, Sir, in the State of West Bengal, at least one lakh tonnes of potatoes have to be purchased. Otherwise, the problem will not be solved. I would like to know from the hon. Minister whether he would consider increasing the purchase of potatoes to one lakh tonnes.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to ask a clarification from the Minister regarding purchase of potatoes in the State of Punjab. The state of affairs in Punjab is very bad as far as potato farmers are concerned. There is no purchase of potatoes, NAFED has not entered the market and the sugar content in potato is so high that it is not profitable or sought out by foreign markets. Unless the sugar content in potato comes down in the State of Punjab, we are going to have a glut all over the countryside. So, I would like the Minister to clarify and advertise as to what he is doing to lessen the content of sugar in potato.

Secondly, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that till the Wagha border with Pakistan and other Islamic countries is not opened, potato growing is going to be non-profitable in Punjab. So, I would appeal to the Government of India to open the border at Wagha and see that potato and other agricultural produce go to Islamic countries.

श्री अजित सिंह : सभापति महोदय, इस बार सदस्यों की चिन्ता आलू के बारे में उचित है। उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल में ही नहीं, पंजाब में भी यह समस्या आई है। आलू की प्रोडक्शन कॉस्ट किसानों को नहीं मिल रही है। पहली बात यह है कि खाड़ी के देशों में जो आलू का निर्यात होना था, उसके बारे में सब को मालूम है कि वहां क्या समस्या है। वहां आलू निर्यात करने में बाधा पड़ी है।

आगरा के सांसद ने जो सवाल उठाया कि खरीदारी नहीं हो रही है, सही बात है कि खरीदारी शुरु होने की जब घोाणा हुई थी, उसमें थोड़ी देर हुई। मैं उन्हें जानकारी देना चाहूंगा कि हमने कम से कम आगरा डिविजन में पिछले हफ्ते यहां से अधिकारी भेजे थे। नैफेड कोआपरेटिव संस्था है तथा डायरैक्टली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है लेकिन यहां से अधिकारी वहां भेजे थे। आगरा डिविजन में ऐसे केन्द्र खुल चुके हैं। वहां 1750 मीट्रिक टन की खरीदारी हुई है लेकिन इस प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार टच में हैं। मैंने वहां की मुख्यमंत्री और प्रोडक्शन कमिश्नर से इस बारे में बात की है। पिछले कई दिनों से उन्होंने मीटिंग बुला कर और अफसरों को पैसा देकर जिलों में भेज दिया है जिससे खरीदारी शुरु हो सके। जहां तक वैस्ट बंगाल का सवाल है, 20 हजार मीट्रिक टन की बात â€¦ (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वहां 40 लाख टन से ज्यादा उत्पादन हुआ है। कम से एक लाख टन परचेज करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अजित सिंह : बीस हजार मीट्रिक टन प्रदेश सरकार से बातचीत करके तय हुआ है और जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ज्यादा खरीद करने की जरूरत है तो हम प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे। जो आलू नैफेड और सरकारी संस्थाओं द्वारा खरीदा जा रहा है, वह मार्केट इन्टरवैन्शन सिस्टम के अंतर्गत है। अगर इसमें नुकसान होता है तो केन्द्र तथा राज्य सरकार पचास-पचास प्रतिशत वहन करती हैं। पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई रिक्वैस्ट नहीं की है।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, the Congress Government in Punjab is not farmer friendly...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

श्री अजित सिंह : केवल उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल सरकारों से रिक्वैस्ट आई थी। वहां बातचीत करके तय हुआ है। यह सही बात है कि उत्तर प्रदेश में चिंताजनक स्थिति है और जरा देरी हुई है। लेकिन पिछले सप्ताह यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का बयान संतोाजनक नहीं है। हम आपकी मार्फत जानना चाहते हैं कि 22 फरवरी से आलू की खरीद का काम होना थाâ€¦ (व्यवधान)आगरा में आज से खरीद शुरू हुई है। किसान परेशान हैं।

डॉ. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : उत्तर प्रदेश के किसान बहुत परेशान हैं।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि माननीय मंत्री जी के बयान के बाद इस बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

श्री रामजीलाल सुमन : यह कोई मामूली बात नहीं है। वहां कई किसानों ने आत्महत्या करने की कोशिश की हैं। यह बहुत गंभीर सवाल है। आप मेहरबानी करके राज्य सरकार से जो रपट आई हैं, उसके बारे में अपने तरीके से जानकारी हासिल करिये। वहां किसान बहुत परेशान हैं। यह किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है। मैं

कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी आपके पास जो जानकारी आई हैं वह राज्य सरकार की मार्फत आई हैं। हमारी प्रार्थना है कि अगर आपके कोई ऐसा तंत्र हो जो सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर सके, तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा सार्थक होगा। यह जानकारी बिल्कुल असत्य हैं। इसकी सत्यता से कोई संबंध नहीं है। वहां आलू कहां खरीदा गया है। मेरे पास आज के अखबार की कतरन है। आलू खरीद का काम आज से शुरू हुआ है, वहां कोई खरीद नहीं हुई हैं। वहां किसान खुदकुशी कर रहे हैं। एक किसान मर चुका है। तीन-चार किसानों ने मरने की कोशिश की है।â€¦ (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या हुआ, यह बताइये।

सभापति महोदय : प्लीज, आप बैठ जाइये। आप अपनी सीट ग्रहण करिये और मेरी बात सुनिये। माननीय मंत्री जी विाय गंभीर हैं, यह आपने भी स्वीकार किया है और सरकार ने पूरी गंभीरता से इस विाय को लिया है। हम आसन से इतना ही कहना चाहते हैं कि जो सवाल सर्व श्री सुमन जी, आचार्य जी और सरदार सिमरजीत सिंह मान जी ने उठाये हैं, आप उनकी भावनाओं को देखते हुए किसानों के द्वारा आत्महत्या करने की नौबत न आये और एम.आई.एस. स्कीम के तहत जितना संभव हो, ज्यादा से ज्यादा आलू की खरीद हो सके, आप अपने स्तर से .या उच्च स्तर से स्थिति को मॉनीटर करें और जो कोऑपरेटिव सिस्टम है तथा नैफेड आदि है, उन सब चीजों को ध्यान में रखें।

श्री रामजीलाल सुमन : आलू किसान मर रहे हैं, यह बड़ा गंभीर मामला है।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)... (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : सभापति महोदय, इन्हें थोड़ा शिटाचार सिखाया जाना चाहिए। इन्हें बिल्कुल भी शिटाचार नहीं आता। यह कोई तरीका नहीं है।

सभापति महोदय : सुमन जी, सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है और चेयर का भी इसमें ऑब्जर्वेशन आया है, उसके बाद भी आप उठकर खड़े हो रहे हैं। जो गंभीर विाय है, इसे और गंभीर मत कीजिए।